शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा

DIRECTORATE OF URBAN LOCAL BODIES HARYANA

EOMC A/Sadar
Secy. MC B/N ....for n/a
as per rules

ई-मेल द्वारा

DMC, Ambala.
DMC/4763-4765
24/10/25

सेवा में,

1. सभी जिला नगर आयुक्त, हरियाणा राज्य।
2. सभी आयुक्त, नगर निगम, हरियाणा राज्य।

क्रमांकः– डी0जी0 यू0एल0बी0/स्था/3ई/2025/23902 दिनांकः 17/10/2025

विषयः– **पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को दिनांक 01.11.2017 से दिनांक 31.05.2023 तक समान काम समान वेतन का लाभ देने बारे।**

उपरोक्त विषय पर सरकार द्वारा जारी हिदायतें क्रमांक 14/13/2018–4सी I दिनांक 06.04.2018 के सन्दर्भ में।

2. विषयाधीन मामले में सरकार के पत्र यादी क्रमांक 14/13/2018–4सी I, दिनांक 06.04.2018 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायतें दिनांक 03.11.2017 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों/शर्तो के अर्न्तगत "समान काम समान वेतन" का लाभ प्रदान करने के निर्देश जारी किये गये। जिसकी पालना में आपको अनुरोध सहित लिखा जाता है कि सरकार की हिदायत दिनांक 26.06.2014 व इसकी निरन्तरता में जारी पत्र दिनांक 23.07.2014 *(प्रति संलग्न)* के तहत पालिका रोल पर लिये गये सफाई कर्मचारियों को दिनांक 01.11.2017 से प्रशासकीय विभाग के पत्र दिनांक 06.04.2018 *(प्रति संलग्न)* की पालना में "समान काम समान वेतन" का लाभ दिया गया है या नहीं की सूचना शीघ्र–अतिशीघ्र निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

17/10/2025
(दीपक कुमार)
अधीक्षक (स्थापना)
निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकूला।
E-mail id:estb-dulb@hry.gov.in

From

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies, Department.

To

The Director,
Urban Local Bodies, Haryana,
Bays No. 11-14, Sector – 4,
Panchkula.

Memo No. 16/15/2014-2CI
Dated: 26.06.2014

Subject:- **Engagement of Safai Karamcharies directly on contractual basis and recruitment of Safai Karamcharies against vacant posts in municipalities.**

Reference on the subject noted above.

2. After careful consideration on the above said matter, the Govt. has decided as under:-

(i) The Safai Karamcharies working with various municipalities, as on the date of the Hon'ble CM's announcement i.e. 10th November, 2013 would be directly engaged by the concerned municipality, on contractual basis, w.e.f. 1st July, 2014 at the wage rate of Rs. 8100/- per month, in relaxation of the outsourcing policy.

ii) The concerned municipality would take the approval of the competent authority for creation of additional posts of Safai karmacharies, on the basis of the norm of one Safai karamchari for every 400 inhabitants and engage Safai Karamcharies on direct recruitment basis, keeping in view the number of total vacant posts of Safai Karamcharis, number of Safai Karamcharies being deployed directly on contractual basis (as above at Sr. No. 1), actual requirement of manpower and availability of adequate financial resources for payment of wages to them.

iii) All the sewerman of municipalities would be entitled for a risk allowance of Rs. 2,000/- per month, over the above their normal wages.

iv) All Safai Karamcharies would be entitled for two sets of uniform and a set of boots, every year. They would also be provided with requisite sweeping material by the concerned municipality.

Superintendent Committee-I
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Urban Local Bodies Department.

(11)

Endst. No. 16/15/2014-2 C I Dated 26.06.2014

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All commissioners,Municipal Corporations in the State of Haryana.
2. All Deputy Commissioners,in the State of Haryana.
3. All Executive Officers of Municipal Councils in the State of Haryana.
4. All Secretaries of Municipal Committees in the State of Haryana.

Balwant Singh
Superintendent Committee – 1
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

A copy is forwarded to the Chief Secretary to Govt. Haryana, Cabinet Branch w.r.t. his U.O. No. 9/172/2014, dated 24.06.2014 for information and necessary action.

Balwant Singh
Superintendent Committee – 1
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

To

The Chief Secretary to Govt. Haryana,
(in Cabinet Branch).

U.O. NO. 16/15/2014-2 C I Dated 26.06.2014

A copy is forwarded to the Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Public Health Engineering Department, for information and necessary action.

Balwant Singh
Superintendent Committee – 1
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

To

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Public Health Engineering, Department.

U.O. NO. 16/15/2014-2 C I Dated 26.06.2014

16

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चंडीगढ़ ।।

प्रेषित

1) सभी आयुक्त, नगर निगम,
2) सभी उपायुक्त,
3) सभी कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद/ सचिव, नगर पालिका,
हरियाणा राज्य।

यादी कमांक 16/15/2014 - 2 क I
दिनांक 23-7-2014

विषयः ठेकेदारो के माध्यम से सफाई कार्य हेतू नियुक्त सफाई कर्मचारियों को सीधे तौर पर अनुवन्ध आधार पर नियुक्त / नियोजन करने बारे दिशा-निर्देश ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के यादि कमांक 16/15 /2014-2सी0 1 दिनांक 26.06.2014 के निरन्तर में।

2. सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की दिनांक 10.11.2013 को गोहाना रैली में की गई घोषणा के दृष्टिगत पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करते हुए दिनांक 10.11.2013 को ठेकेदारों/एजैण्सीज् के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2014 से अनुबन्ध आधार पर सीधे तौर पर रिक्त पदो के विरूद्ध सम्बन्धित पालिकाओ में नियुक्त करने बारे निर्णय लिया गया है।

3. नगरनिगम/ नगरपरिषद तथा नगरपालिकाएं आवश्यकता अनुसार, अपनी वित्तीय स्थिति एवं सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों में निहित व्यवस्थाओं के दृष्टिगत, 400 व्यक्तियों पर एक सफाई कर्मचारी के अनुपात में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के पद सक्षम प्राधिकारी से सृजित करवाते हुये इन पदों के विरूद्ध पूर्व में ठेकेदारो / एजैण्सीज के माध्यम से दिनांक 10.11.2013 को कार्यरत सफाई कर्मचारियों जो वर्तमान में भी कार्यरत हैं, को एक वर्ष के अनुवन्ध आधार पर नियुक्त करेंगीं । इस अनुबन्ध अवधि का सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जा सकेगा । हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 67 (4) के अंर्तगत सन्वंधित नगर निगम सरकार से तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 एवं हरियाणा नगरपालिका सफाई मजदूर सेवा नियम, 1976 के नियम 3 के अंर्तगत नगर परिषद/नगर पालिकाएं प्रस्ताव पारित करके सम्बन्धित उपायुक्त से स्वीकृत करवाएंगीं ।

4. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी आउट सोर्सिंग नीति में समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा रोजगार विभाग को मांगपत्र भेजने एवं अधिकतम 6 मास की अवधि हेतू सेवा लेने बारे प्रावधानों में सरकार द्वारा छूट प्रदान कर दी गई है।

5. उपरोक्त अनुसार अनुवंध आधार पर नियोजन करते समय निम्न दिशा-निर्देशों अनुसार कार्रवाई की जाए :-

1) दिनांक 10.11.2013 को ठेकेदारों / एजैण्सीज के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को ही अनुवन्ध आधार पर दिनांक 01.07.2014 से सीधी नियुक्ति / नियोजन किया जाए ।
2) सफाई कर्मचारियों को अनुवन्ध आधार पर नियुक्ति / नियोजन करने से पूर्व प्रार्थनापत्र, आयु प्रमाणपत्र लिया जाए तथा संलग्न करारनामा (Agreement Bond) अमल में लाया जाए ।
3) कर्मचारी की पहचान हेतू दो फोटो व दो पहचान-प्रमाण (राशनकार्ड/वोटरकार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसैंस में से कोई भी दो) लिये जायें।
4) नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति होने तक इन कर्मचारियों के साथ वार्षिक आधार पर अनुबन्ध का नवीनीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाये।
5) इन कर्मचारियों को 8100/- रूपये प्रतिमास वेतन तथा प्रत्येक वर्ष दो जोड़ा वर्दी तथा दो जोड़ जूते दिए जाएं ।
6) इन कर्मचारियों को नियमानुसार ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि का लाभ दिया जाये।
7) इन कर्मचारियों का नियमानुसार संबधित सिविल सर्जन से आरोग्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस) लिया जाए ।

6. इस सम्बन्ध में आपको कार्यरत सफाई कर्मचारी/प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित पालिका को दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्र, सफाई कर्मचारी को अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने सम्बन्धी नियुक्ति-पत्र, इकरारनामा तथा नियुक्ति पत्र में वर्णित नियन एवं शर्तों को प्रार्थी द्वारा स्वीकार करने सम्बन्धी प्रापत्रों के प्रारूप इसके साथ संलग्न किए जाते हैं ताकि एकरूपता बनाई जा सके ।

23/7/14

(हस्ताक्षर)
अधीक्षक कमेटी-I
कृते अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चंडीगढ़ ।।

पृ0 कमांक 16/15/2014-2का-I दिनांक 23-7-2014

एक प्रति निदेशक,शहरी स्थानीय निकाय,हरियाणा, पंचकूला को सूचना /आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।

अधीक्षक कमेटी–I
कृते अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चंडीगढ़ ।

-3- -423-
-9-

The Principal Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

To

1. All the Commissioners, Municipal Corporations in the State of Haryana.
2. All the Executive Officers, Municipal Councils in the State of Haryana.
3. All the Secretaries, Municipal Committees in the State of Haryana.

Memo No. 14/13/2018-4C-I
Dated 06.04.2018

Subject: Application of "equal pay for equal work" in respect of specified categories of employees.

******

Reference on the subject cited above.

2. In pursuance of the Haryana Government instructions issued vide letter no. 16/36/2016-3GS-II, dated 3.11.2017, the Government has decided to implement the provisions of the aforesaid policy decision in respect of employees of all the Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees and Improvement Trusts in the State of Haryana as under:-

"Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 213 of 2013 titled 'State of Punjab Versus Jagjit Singh' issued judgment dated 26.10.2016 which clarified that the principal of equal pay for equal work constitutes a clear and unambiguous right and is vested in every employee, whether engaged on regular or temporary basis if he qualifies the application of the parameters of the principal of 'equal pay for equal work' as summarised by Hon'ble Supreme Court of India in paragraph 42 of the said judgment.

State Government has considered the matter and decided as under:

i) The principal of 'equal pay for equal work' shall be applicable to the contractual employees subject to application of parameters of the principal of 'equal pay for equal work' as summarised in para 42 of the judgement. In respect of contractual pay, these employees shall be entitled to the minimum of the pay-scale of the categories to which they belong but would not be entitled to any of the allowances attached to the post.

ii) 'Equal pay for equal work' principal shall be initially applied to employees engaged under outsourcing policy Part-II w.e.f. 1.11.2017.

iii) A committee has been constituted vide notification No. 16/36/2016-3GS-II, dated 06.10.2017 to decide on cases of other categories of employees (i.e. other than those covered in Part of Outsourcing Policy) to whom this principal of 'equal pay for equal work' shall apply.

All the Departments/Boards/Corporations/Autonomous Bodies who have engaged manpower under Part-II of the outsourcing policy are advised to apply the principal of 'equal pay for equal work' in respect of employees engaged under Part-II of the outsourcing policy w.e.f. 01.11.2017.

In respect of application of the principal of 'equal pay for equal work' to any other category of employees, the concerned Departments/Boards/Corporations/Autonomous Bodies may approach the committee constituted for the purpose.

This issues with the concurrence of Finance Department vide their U.O. No. 2/33/2017-1FG-1/32793, dated 03.11.2017.

It is made clear that all the financial implications arising on granting of the aforesaid benefits will be borne by the concerned Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees and Improvement Trusts from their own financial resources and no grant or grant in aid will be provided by the Government.

Superintendent Committee – I,
for Principal Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Dated 06.04.2018

...: No. 14/13/2018-4C-I

A copy is forwarded to Director General, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula, Bays No. ...-..., Sector-4, Panchkula w.r.t. your single File system Dy. No. DLB-6542, dated 08.02.2018 for ...information and further necessary action.

Superintendent Committee – I,
for Principal Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.